of women entrepreneurs, preparation of a shelf of viable projects, facilitating the availability of credit, promotion of marketing through tie-up, strengthening of women's cooperative and arranging training of beneficiaries in concerned trades, project formulation, and financial management. Central Government provides 49 per cent of the share capital. It is the responsibility of the State Governments to set up such Corporations. In Uttar Pradesh, a Women Development Corporation has been set up in 1988. No Corporation has yet been set up in Bihar.

मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हेतु योजना

*213. **श्री अजीत जोगी :**
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय स्थिति में सुधार लाने से संबंधित कोई योजना स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त पर्यावरण सुधार से संबंधित अन्य कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश के अन्य राज्यों के लिये भी ऐसी ही कोई योजना तैयार की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय स्थिति मे सुधार से संबंधित स्कीमें राज्य के योजना कार्यक्रमों का एक भाग है । जिन स्कीमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है उनका विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधी इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों को भी प्रदान की गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश में जिन स्कीमों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है :

1. नमभूमि-भोज झील का संरक्षण ।

2. क्षेत्रीय तथा तकनीकी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के पर्यावरण विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता ।

3. खतरनाक अपशिष्टों के लिए प्रबंध ढांचे का सृजन ।

4. पर्यावरणीय शिक्षा तथा जागरूकता तथा पर्यावरण सूचना केन्द्र ।

5. इन्द्रावती तथा कान्हा बाघ रिजर्व ।

6. आदिवासी विकास के लिए बेनिफिशियरी ओरिएंटिड स्कीम ।

7. जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत संरचना का विकास ।

8. वन्यजीव सुरक्षा ।

9. परती भूमि विकास ।

नई शिक्षा नीति के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार किया गया नीति-पत्र

*214. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति के संबंध में "राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान" से एक नीतिपत्र तैयार कराया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति-पत्र को प्रकाशित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ; और